आत्मनिर्भर भारत अभियान की अवधारणा–प्रमुख क्षेत्र एवं संभावनाएँ

गाँधीजी राय

Ikjk'k *'आत्मनिर्भर भारत अभियान' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह दूरदर्शी दर्शन है जिसके साकार होने से भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अवतरित होकर अपनी छवि को निखार सकेगा। इस अभियान को सफल बनाकर भारत अपनी बुलंदियों और उपलब्धियों को छूते हुए सदियों पुरानी अपने 'वसुधैव कुटुंबकम्' के आदर्श को पुनर्स्थापित कर पूरे विश्व को प्रभावित कर सकेगा। इस आलेख में यह बताया गया है कि इस अभियान के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी तथा मांग की अवधारणा संबंधी पहल से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित अन्य देशी उद्योगों का जीर्णोद्धार होगा और रोजगार के नए अवसरों के सृजन से बेरोजगारी से जूझते देश की युवा शक्ति को अपनी बुद्धि और कौशल को प्रदर्शित करने का एक अवसर मिलेगा। इस अभियान के लिए घोषित आर्थिक पैकेज यदि सही दिशा में संचालित हुए तो निश्चित रूप से देश आत्मनिर्भर बनकर विश्व के अन्य देशों को भी सहायता करेगा। इसके सफल क्रियान्वयन से गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, किसान, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोग, कस्तकार, कुटीर, लघु एवं मध्यम वर्गीय उद्योग लाभान्वित होंगे। यदि देश के लोग अपने संकल्प और प्रतिबद्धता से इस अभियान में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ता बनाकर एक ब्रांड के रूप में वैश्विक प्रतियोगिता में शामिल करें तो 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।*

भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' वह दूरदर्शी दृष्टि (vision) है जो देश को हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होने की मंत्रणा देती

है। इस अभियान का उद्देश्य देश को उन सभी विदेशी निर्भरताओं को समाप्त करना है जिसके चलते आज भारत का ज्यादातर व्यापार वाह्य देशों पर निर्भर है। यह अभियान वाह्य वस्तुओं पर निर्भरता को नियंत्रित करते हुए अच्छी गुणवत्ता वाले *स्वदेशी उत्पादों* को अपनी भूमि पर तैयार करने की सीख देता है। यदि देश अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप छोटे-बड़े सभी उत्पादों का देशांतर्गत ही उपार्जन एवं निर्माण करने लगे तो विश्व की कोई भी शक्ति देश को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकेगी। कोरोना महामारी से उत्पन्न विवशता और आर्थिक तनाव को दूर करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' प्रारंभ करने की घोषणा की। इस अभियान को सफल बनाने के लिए उन्होंने जिस 20 लाख करोड़ रुपये के *राहत पैकेज* की घोषणा की, वह देश की *सकल घरेलू उत्पाद* का लगभग 10 प्रतिशत है। अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रणाली, जनसांख्यिकी तथा मांग संबंधी *पाँच* स्तंभों के सुदृढ़ीकरण के आलोक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का प्रयास किया है। वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री *श्रीमती निर्मला सीतारमण* ने 13-17 मई 2020 तक प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज का विवरण *पाँच* किस्तों में घोषित कर इस अभियान के कार्यान्वयन की शुरुआत की। यह अभियान मुख्यतः भारतीय संसाधनों से निर्मित वस्तुओं को भारत में ही उपयोग में लाने की मंत्रणा देता है। इसके अंतर्गत घोषित विविध कार्यक्रमों/पहलों से स्पष्ट है कि इस अभियान का उद्देश्य भारत के उद्योगों में सुधार लाकर युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना है। इस अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, गरीबों, श्रमिकों और किसानों के कल्याण के लिए की गई घोषणाएँ आत्मनिर्भर भारत का मूलमंत्र है। इस अभियान की सबसे बड़ी देन इसमें वैश्वीकरण को समाहित करना है जिसमें विश्व कल्याण की बात कही गई है। जहाँ प्रथम चरण में स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रानिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे स्थानीय क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया है, वहाँ *द्वितीय चरण* में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, इस्पात जैसे क्षेत्रों के उन्नयन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के लिए घोषित पैकेज का बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में देने की योजना है। सरकार बैंकों को ऋण वापसी की गारंटी के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में ब्याज दर में दो प्रतिशत स्वयं वहन करेगी। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने अपने घोषित आर्थिक पैकेज में किसी को भी नगद बहुत कम दिया है, लेकिन अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए दिए गए उनके मंत्र से न तो देश घाटे में रहेगा और न कोई वित्तीय मनमानी करेगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 मई 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा के निम्नलिखित जिम्मेवार कारण थे–

1- dkfoM-19 egkekjh dk fo'o0;kih iHkko& चीन के वुहान शहर से एक स्थानीय बीमारी के रूप में शुरू हुआ *कोविड -19* ने कुछ हफ्तों में ही पूरे विश्व को अपने प्रभाव में ले लिया। चार महीने के अंदर ही 26 जून 2020 तक विश्व भर के 188 देशों में 97 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हुए और 4.92 लाख लोग मारे जा चुके थे।[1] उस समय इस महामारी का इलाज या टीका नहीं होने के कारण तीव्र गति से इसका फैलाव होता गया। वैश्विक स्तर पर इसका स्पष्ट प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल के रूप में दिखाई दिया। इसके बढ़ते फैलाव के डर से विमान यात्राएँ बंद कर दी गईं, पर्यटन थम गया और मनोरंजन जैसे संबंधित उद्योग बंद हो गए। विश्व के देशों ने न सिर्फ अपनी-अपनी सीमाएँ बंद कीं, वरन् जनता के आवागमन पर भी अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। *अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन* के एक अनुमान में 1.25 अरब कामगारों अर्थात वैश्विक श्रम बल का लगभग 38 प्रतिशत भाग पर रोजगार का संकट छा गया। वैश्विक अर्थव्यस्था की रीढ़ कहलाने वाले तेल उद्योग भी गंभीर संकट से लड़खड़ाने लगा। अमेरिका सहित अन्य बड़े-छोटे सभी देशों को वायरस की तगड़ी मार झेलनी पड़ी। भारत में सबसे बुरी स्थिति तब हुई जब *लॉकडाउन* लगाया गया। भारत अपने जरूरी कच्चे माल के लिए चीन पर आश्रित था। कोरोना संकट का प्रभाव सिर्फ भारत के प्रवासी मजदूरों पर ही नहीं पड़ा, वरन् सभी तबके के लोग और उनके उद्योग धंधे भी प्रभावित हुए और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कई आवश्यक उत्पादों के लिए चीन पर आत्मनिर्भरता के चलते देश की स्थिति बिगड़ गई। भारत के पास मौजूद विशाल जनसंख्या के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, तकनीकी, पर्यावरण संरक्षण की संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* ने एहसास किया कि चीन पर निर्भरता कम करनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नजरअंदाज किए बिना आत्मनिर्भरता व स्वदेशी पर आधारित अर्थव्यवस्था तैयार करनी चाहिए।

2- n'k dh cgky vFk0;oLFkk& अप्रैल 2020 तक कोरोना महामारी विश्व के लिए परेशानी का सबब बन गई। महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया। *सांख्यिकी मंत्रालय* के अनुसार वित्त वर्ष 2020 की चौथी-तीमाही में भारत की वृद्धि दर घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई।[2] *अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष* ने अनुमान लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5 की दर से सिकुड़ जाएगी।[3] कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश में लगे *लॉकडाउन* ने कई सरकारी और निजी व्यवसायों एवं उद्योगों को चौपट कर दिया। इससे घरेलू *आपूर्ति* और *मांग* पर पड़े प्रभाव ने देश की आर्थिक वृद्धि दर को भी बुरी तरह प्रभावित किया। *लॉकडाउन* का सबसे ज्यादा प्रभाव अनौपचारिक क्षेत्र

पर पड़ा। उल्लेखनीय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का 50 प्रतिशत *सकल घरेलू उत्पाद* (GDP) अनौपचारिक क्षेत्र से ही आता है। इसके चलते *लॉकडाउन* प्रारंभ होने के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री *पीयूष गोयल* ने देश में पाँच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को साकार करने के लिए घरेलू उद्योग को अधिक आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया।[4] लॉकडाउन के कारण करीब 12 करोड़ लोगों ने रोजगार खो दिया। पूरे देश में 45 प्रतिशत से अधिक परिवारों ने आय में गिरावट दर्ज की। पहले 21 दिनों के *पूर्ण लॉकडाउन* के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को हर दिन 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की हानि होने की आशंका थी। पूर्ण लॉकडाउन के तहत भारत के 2.8 ट्रिलियन आर्थिक संरचना का एक चौथाई से भी कम गतिविधि कार्यात्मक थी। अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्मचारी और दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक जोखिम वाले लोग हैं। देश भर में बड़ी संख्या में किसान जो विनाशशील फल-सब्जी उगाते हैं, उन्हें भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा।[5] महामारी से ठीक पहले, सरकार ने कम विकास दर और कम मांग के बावजूद 2024 तक अर्थव्यवस्था को अनुमानित 2.8 ट्रिलियन से पाँच ट्रिलियन तक बदलने का लक्ष्य रखा था।

3- okå fuHk'jrk& कोरोना ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। जब से संकट गहराया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शिथिल होता गया और इसने भारत जैसे अनेक राष्ट्रों को अपने पैरों पर खड़ा होकर वाह्य निर्भरता को कम करने के लिए उत्प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नजरअंदाज किए बगैर कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए आत्मनिर्भरता और स्वदेशी अर्थव्यवस्था तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की आवश्यकता महसूस की। भारत को अपने *विनिर्माण क्षेत्र* को नए सिरे से तैयार कर अर्थव्यवस्था की गति में तेजी लाना इस अभियान का प्रेरक तत्त्व रहा है।

4- fo'kky tul[;k& अपनी विशाल जनसंख्या के साथ भारत के पास स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वच्छ तकनीक, पर्यावरण संरक्षण में भारी संभावनाएँ निहित हैं जिन्हें नए ढंग से खंगाल कर इसका इस्तेमाल देश के पुनर्निर्माण में किया जा सकता है।

5- lkekftd lqj{kk O;oLFkkvksa esa [kkfe;k& देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में खामियों के चलते समृद्धि की श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर पड़े समाज के कमजोर तबकों पर कोरोना महामारी का सबसे अधिक बोझ पड़ा। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की शुरुआत की।

6- Lokoyacu& 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' से उत्प्रेरित होकर देश प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर अपने पैरों पर खड़ा होगा। एक स्वावलंबी देश ही वैश्विक स्तर पर अपने सम्मान की रक्षा कर सकता है। भारत के आत्मसम्मान की भावना को साकार करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के लिए तैयार करेगी। छोटी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बल देकर देश कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता होने का प्रयास करेगा।

7- dVhj] l{e] y?k ,o e/;e m|ek d l'kfDrdj.k d fy,& 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में सिर्फ कुटीर उद्योगों को ही पुनर्जीवित करना नहीं था, वरन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देकर देश में चल रहे विकास की गति को आगे बढ़ाना था। कुटीर उद्योगों के साथ-साथ देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थिति बहुत खराब थी जिसमें सुधार लाकर नरेंद्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को सफल बनाने का प्रयास किया है। यदि प्रधानमंत्री द्वारा इस क्षेत्र में की गई घोषणाएँ *साकार* होती हैं तो भारत निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़ा होकर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान सुनिश्चित कर सकेगा।

8- ol/kso dVcde& ^आत्मनिर्भर भारत अभियान' 'वसुधैव कुटुंबकम्' की संकल्पना में विश्वास करता है। भारत विश्व का एक हिस्सा होने के चलते जब प्रगति करता है तब ऐसा करके वह विश्व की प्रगति में योगदान देता है। 25 सितंबर 2021 को 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित करते हुए *नरेंद्र मोदी* ने कहा था, ''जब भारत विकास करता है तब विश्व भी विकास करता है। जब भारत *रिफॉर्म्स* करता है तब विश्व भी ट्रांसफॉर्म होता है।''[7] 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' वैश्वीकरण के बहिष्कार के बदले विश्व के विकास में मदद करता है। उल्लेखनीय है कि *महात्मा गाँधी* ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से *चरखा समितियों* तथा *लघु उद्योगों* से जुड़ने की प्रेरणा देकर आत्मनिर्भरता को देश की स्वतंत्रता के लिए एक महत्त्वपूर्ण औजार माना था। उन्होंने कहा था कि एक आत्मनिर्भर देश ही सशक्त देश बनता है। भारत की आजादी की लड़ाई में गाँधीजी द्वारा संचालित *'स्वदेशी आंदोलन'* में उन्होंने लोगों से विदेशी वस्तुओं पर निर्भर न रहकर भारत में बनी वस्तुओं पर निर्भर रहने की अपील की थी। गाँधीजी सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ही नहीं करते थे, वरन आत्मनिर्भर भारत की तरफ उन्होंने पहला कदम भी उठाया था। 'स्वदेशी आंदोलन' के तहत वे विदेशी कपड़ों के स्थान पर अपने हाथ से बुने हुए कपड़े पहनते थे। वे कुटीर उद्योगों के विकास

के हिमायती थे और उनका विकास कर वे भारतीयों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे।[8] प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' भी गाँधीजी के सपने को पूरा करने का एक प्रयास है।

9- **urRo vkj eukcy dk cuk, j[kus dh fy,&** देश के नेतृत्व और देशवासियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए भी 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की शुरुआत नए ढंग से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मान्यता है कि भारत की पुरानी संस्कृति और पहचान को यदि वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है तो इसके लिए देशवासियों के *संकल्प* और *प्रतिबद्धता* की आवश्यकता है। देशवासी अपने *संकल्प* और *प्रतिबद्धता* से न सिर्फ प्रत्येक क्षेत्र में स्वावलंबी होकर अपने पैरों पर खड़ा होंगे, वरन वैश्विक स्तर पर भी अपने नेतृत्व से भारत की उपलब्धियों का बखान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा को चरितार्थ करेंगे।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के स्तंभ और बहुआयामी क्षेत्र

हर मामले में स्वावलंबन का संदेश देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की इमारत के निम्नलिखित *पाँच* प्रमुख स्तंभ हैं–

1- **vFkZ;oLFkk&** अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए एक ऐसा सशक्त साधन है जिसमें सुधार और परिवर्तन लाकर देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। देश की मौजूदा मिश्रित अर्थव्यवस्था में बदलाव लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की वकालत की है जो 'वृद्धिशील परिवर्तन' (incremental change) की जगह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लंबी छलांग (quantum jump) लगाए।[9]

2- **vk/kkjHkwr lajpuk&** प्रधानमंत्री ने एक ऐसी आधारभूत संरचना का आह्वान किया जो आधुनिक भारत की पहचान बनकर विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर सके।

3- **i.kkyh&** देश में एक ऐसी आधुनिक प्रणाली हो जिसमें समाज और देश में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाने की क्षमता हो। ऐसी प्रणाली जो 20वीं सदी की रीति-नीति को छोड़ते हुए 21वीं सदी के सपनों को साकार कर सके।

4- **Tkulkf[;dh&** विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की जीवंत जनसांख्यिकी सबसे बड़ी ताकत और आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा का अनवरत स्रोत है जिसका उपयोग कर भारत आत्मनिर्भर बनकर 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना को साकार कर सकता है।

5- **Ekkax&** देश की अर्थव्यवस्था में *मांग* और *पूर्ति* की प्रक्रिया की पूरी क्षमता

से उपयोग कर भारत वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भरता के अभियान को सफल बना सकता है। यह तभी संभव होगा जब देश में मांग बढ़ाने और उसे पूरा करने के लिए हमारी आपूर्ति कड़ी के हर हितधारक सशक्त हो। भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार और मांग दोनों है जिसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल कर 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को सफल बनाया जा सकता है।

बहुआयामी क्षेत्र

12 मई 2020 को देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि ये विशेष आर्थिक पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की अहम कड़ी' के तौर पर काम करेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा इससे पूर्व में की गई घोषणाओं और *रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया* द्वारा लिए गए निर्णयों से जुड़ी राशि को मिला देने से यह विशेष आर्थिक पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपये का है जो भारत के सकल घरेलु उत्पाद के करीब 20 प्रतिशत के समतुल्य है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित यह आर्थिक पैकेज देश के विकास से संबंधित बहुआयामी क्षेत्रों से संबंधित है। यह आर्थिक पैकेज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के पुनर्जीवन और विकास से संबंधित है जो करोड़ों भारतीयों की आजीविका का प्रमुख साधन है। भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर केंद्रित यह आर्थिक पैकेज कुटीर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, मजदूरों, मध्यम वर्ग सहित विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के आह्वान के दौरान जिस 'वोकल फॉर लोकल' का नारा दिया, उससे स्थानीय उत्पादों का गर्व से प्रचार करने और इन उत्पादों को वैश्विक बनाने में मदद मिलेगी। स्थानीय उत्पाद देशवासियों की सिर्फ जरूरत ही नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मवारी भी है। जब तक देशवासी स्थानीय उत्पाद स्वयं नहीं खरीदेंगे और गर्व से उनका प्रचार नहीं करेंगे तबतक देश अपने पैरों पर खड़ा होकर उत्थान नहीं कर सकता। घरेलू बाजार में नेतृत्व के लिए स्थानीय *ब्रांड* को तकनीकी विशेषता, बेहतर गुणवत्ता और किफायती दर पर निर्मित करके ही 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के सपने को साकार किया जा सकेगा।

आर्थिक पैकेज का विवरण

वित्त एवं कॉपोरेट कार्य मंत्री *श्रीमती निर्मला सीतारमण* ने 13-17 मई 2020 तक प्रतिदिन पत्रकार सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत पैकेज का विवरण निम्नलिखित *पाँच* किस्तों में दिया–[10]

1- iFke fdLr& 13 मई 2020 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के सशक्तिकरण हेतु अनेक घोषणाएँ कीं–
1- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों सहित अन्य व्यावसायों के लिए तीन लाख

करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूँजी की सुविधा **nk-nk** लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ के गौण ऋण का प्रावधान **3-** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इक्विटी फंडिंग (Equity Funding) के तहत 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक 'फंड ऑफ फंड्स' (Fund of Funds) खोलने का आह्वान **4-** इसके तहत निवेश की सीमा बढ़ाकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की परिभाषा को संशोधित करते हुए पूर्ण बिक्री का एक अतिरिक्त मानदंड पर बल **5-** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए *ई -मार्केट लिंकेज* को बढ़ावा **6-** 600 करोड़ रुपये से कम मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीददारी में निविदा नियमों में संशोधन का प्रावधान **7-** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत नियोक्ता व कर्मचारी दोनों के वेतन से जून-जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन में 12-12 प्रतिशत का योगदान **8-** सभी उद्यमों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अनिवार्य भविष्य निधि अंशदान को तीन माह तक 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा **9-** भारत सरकार के 100 प्रतिशत गारंटी के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), हाऊसिंग फाइनांस कंपनी (HFC) तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFI) के लिए 30,000 रूपये की एक विशेष तरलता योजना का प्रारंभ **10-** गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)/सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (MFI) की देनादारियों के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी *योजना 2.0* का प्रावधान **11-** पॉवर फाइनेंस कॉपोरेशन (PFC) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) के तहत विद्युत विरतण कंपनी (DISCOM) में दो समान किस्तों में 90,000 करोड़ रुपये तक की तरलता सुलभ कराने का प्रावधान **12-** रेलवे, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से जुड़े ठेकेदारों को छह माह की राहत **13-** रियल स्टेट परियोजनाओं को राहत का प्रावधान तथा **14-** व्यवसाय के लिए कर राहत की घोषणा।

2- f}rh; fdLr& 14 मई 2020 को प्रवासियों , किसानों, छोटे कारोबारियों और फेरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदमों की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रवासी कामगारों के लिए मई और जून 2020 के लिए प्रति कामगार दो किलोग्राम की दर से खाद्यान्न और प्रति परिवार एक किलोग्राम चना का मुफ्त आवंटन किया गया। इसके अंतर्गत अन्य घोषणाओं में इन प्रवासियों को भारत की किसी भी उचित मूल्य वाले दुकान से राशन खरीदने, प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए की आवास परिसरों की योजना, 50 हजार से कम शिशु मुद्रा लेने वालों को 12 महीनों

के लिए दो प्रतिशत ब्याज की छूट, फेरीवालों के लिए 5,000 करोड़ की ऋण सुविधा, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत धातु अक्रिय गैस (MIG) के लिए *क्रेडिट लिंक्ट सब्सिडी* योजना के विस्तार के माध्यम से आवासन क्षेत्र और मध्यम आय समूह को 70,000 करोड़ का प्रोत्साहन, क्षतिपूरक वरीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूँजी का प्रावधान तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2. 5 करोड़ किसानों को दो लाख करोड़ का ऋण प्रोत्साहन की घोषणा।

3- r'rh; fdLr& 15 मई 2020 को वित्त मंत्री ने – **1-** किसानों के लिए कृषि द्वारा आधारभूत ढाँचे पर केंद्रित एक लाख करोड़ का कृषि *आधारभूत ढाँचा कोष* **2-** सूक्ष्म, खाद्य उपक्रमों (FME) के औपचारीकरण हेतु 10,000 करोड़ रुपये की योजना **3-** प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान **4-** *खुरपका* और *मुँहपका* रोग (FMD) तथा *ब्रुसेलोसिस* के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 13,343 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रावधान **5-** पशुपालन बुनियादी ढाँचा विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान **6-** औषधीय या हर्बल खेती के प्रोत्साहन के साथ 4,000 करोड़ का परिव्यय **7-** मधुमखी पालन संबंधी पहल के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान **8-** टॉप (TOP) अर्थात टमाटर, प्याज और आलू सहित सभी फलों और सब्जियों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स (Opretion Greens) के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान तथा **9-** कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार हेतु (*i*) किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन (*ii*) किसानों को विपणन का विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार तथा (*iii*) कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन।

4- prFk fdLr& 16 मई 2020 को वित्त मंत्रालय द्वारा *आठ क्षेत्रों* कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, बिजली क्षेत्र, सामाजिक आधारभूत ढाँचा तथा अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में ढाँचागत सुधारों के लिए घोषणा कर 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को साकार करने का प्रयास किया गया।

5- ipe fdLr& 17 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के आर्थिक पैकेज की पाँचवीं और आखिरी किस्त की घोषणा करते हुए पूरे 20 लाख करोड़ रुपये का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए *मनरेगा* के अंतर्गत 40,000 करोड़

रुपये का आवंटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार संबंधी पहलें, *कोविड -19* के बाद समानता के साथ प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा, दिवालिया एवं *शोधन अक्षमता संहिता* (IBC) से संबंधित उपायों, कंपनी अधिनियम के तहत हुई भूल को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर, कंपनियों के लिए कारोबार में सुगमता लाने का प्रयास, नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति की घोषणा तथा राज्य सरकारों के सहायतार्थ 2020-21 के लिए उनके ऋण की सीमा में तीन प्रतिशत से पाँच प्रतिशत की वृद्धि।

'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा पर केंद्रित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' स्थानीय गुणवतापूर्ण उत्पादों और वैश्विक स्तर पर उन्हें प्रतियोगी बनाने पर केंद्रित है। यह 'वोकल फॉर लोकल' के संदेश के साथ स्थानीय और स्वदेशी विनिर्माण, स्थानीय बाजार तथा स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बल देते हुए देशवासियों को उत्प्रेरित करता है कि अपने स्थानीय उत्पादों में गुणवता लाते हुए वे उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतियोगी बनाने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य से इस अभियान से संबद्ध आर्थिक पैकेज *भूमि* (Land), *श्रम* (Labour), *तरलता* (Liquidity) और *कानूनों* (Laws) पर केंद्रित होकर कुटीर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों सहित अन्य उद्यमों, मजदूरों तथा सभी वर्गों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के लिए तैयार करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के इस दौर में कामयाबी के लिए देशवासियों के *मनोबल* (Moral) को बढ़ाना होगा। 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के विशेष पैकेज संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों के मजदूरों तथा प्रवासियों को सशक्त करने की दिशा में केंद्रित है। इस अभियान के प्रमुख केंद्र देश के वे लोग हैं जिन्हें अपने उत्पादों को न सिर्फ खरीदना है, बल्कि स्वनिर्मित गुणवत्तापूर्ण उत्पादों से गौरान्वित होकर उन्हें अन्यों को भी इन उत्पादों को खरीदने के लिए उत्प्रेरित करना है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा के लिए अपने *ब्रांड* उत्पाद को विशेषज्ञता, बेहतर गुणवत्तापूर्ण और किफायती मूल्यों पर निर्मित करना होगा।

संभावनाएँ

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत घोषित विभिन्न कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के बाद भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनकर महात्मा गाँधी के आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करेगा। इस अभियान' के लिए घोषित कार्यक्रमों के अनुरूप कृषि और अन्य क्षेत्रों को विकसित कर तथा औद्योगिक विकास के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाकर नरेंद्र मोदी का यह सपना यदि साकार हो गया तो भारत निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़ा होकर वैश्विक शंखनाद करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों की *पैकेजिंग* या उनसे बनने वाले अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर छोटे

औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है। 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में 21वीं सदी में वैश्विक स्तर पर उभरते भारत की तस्वीर थी जिसमें भारत को अपनी पहचान बनानी है। यह अभियान भारत को स्वावलंबी बनाकर विश्व की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत इस अभियान के उद्देश्यों को चरितार्थ कर वैश्विक स्तर पर भी अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। 25 सितंबर 2021 को *संयुक्त राष्ट्र महासभा* के 76वे सत्र को संबोधित करते हुए *नरेंद्र मोदी* ने कहा था, ''जब भारतीयों की प्रगति होती है तो दुनिया के विकास को भी गति मिलती है''।[11] इस अभियान का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है कि यह आत्मकेंद्रित व्यवस्था के स्थान पर संपूर्ण मानवता के विकास की वकालत करता है। इस अभियान की सफलता के लिए घोषित *पाँच* स्तंभों के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों के सही क्रियान्वयन से भारत स्वावलंबी होकर सदियों पुरानी अपनी ''वसुधैव कुटुंबकम्'' की अवधारणा को साकार करेगा जो इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और बेहतर भविष्य की संभावनाएँ हैं। भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों का देश रहा है। स्वतंत्रता के बाद देश की गरीबी और भुखमरी को दूर करने के लिए ही *गाँधीजी* ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था। प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* का यह अभियान देशवासियों को हर क्षेत्र में स्वयं पर निर्भर रहने का संदेश देता है। ऐसी संभावना है कि इस अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन से देश को अनेक फायदे होंगे– **1-** देशांतर्गत प्रत्येक श्रेणी के उद्योगों की संख्या में उतरोत्तर वृद्धि होगी **2-** देश को अपनी आवश्यकताओं के लिए अन्य देशों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी **3-** बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना से देश में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे **4-** आत्मनिर्भर बनकर भारत गरीबी और भुखमरी से मुक्त होकर वैश्विक प्रतियोगिता में अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा **5-** अपने पैरों पर खड़ा होकर बड़ी मात्रा में चीजों का भंडारण कर सकेगा **6-** अन्य देशों से आयात कम और निर्यात अधिक होगा **7-** देश में स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण से तरक्की को एक नया मुकाम मिलेगा तथा **8-** संकट के दिनों में बाहरी देशों पर निर्भरता की कमी से राष्ट्रीय गौरव एवं आत्मसम्मान में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत बहुआयामी क्षेत्रों के विकास के लिए घोषित विविध कार्यक्रमों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह अभियान नए भारत के सपने को साकार करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के लिए सबसे बड़ी देन है। इसके सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन से देश निश्चित रूप से स्वावलंबी बनकर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इसका सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू इसका आत्मकेंद्रित

न होकर संपूर्ण मानवता के विकास के लिए वकालत करना है। इसके प्रति देशवासियों की आत्मीयता, लगाव, समर्पण और संकल्प से भारत सदियों पुरानी अपनी ''वसुधैव कुटुंबकम्'' के आदर्श को साकार करते हुए 21वीं सदी में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। इसके लिए देशवासियों को *संकल्प* लेना होगा कि वे इसके सफल क्रियान्वयन के लिए अनवरत प्रयास करते रहेंगे। प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* ने भी आह्वान किया था, ''साथियों, आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है''। इसकी घोषणा के बाद से ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में उसका प्रभाव दिखने लगा है। रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम से दुश्मनों के हौंसले पस्त होने लगे हैं। उदाहरणार्थ समुद्र में ट्रायल पर चल रहा *आईएनएस विक्रांत* के रूप में देश का दूसरा एयरक्राप्ट कैरियर पूरी तरह से देश में निर्मित है और आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर शीघ्र ही भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है।[12] भारत का पहला विमानवाहक युद्धपोत भी *आईएनएस विक्रांत* के नाम पर ही है।

संदर्भ ग्रंथ

1. कोविड-19 महामारी की दलदल में फंसी अर्थव्यवस्था, https://www.downtoearth.org.in
2. भारत में कोरोना वायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव, https://hi.m.wikipedia.org
3. उपरोक्त
4. अहमद, जुबैर (1 मई 2020), ''कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था स्वदेशी की तरफ जाएगी?'' BBC News हिंदी, मूल से 27 जून 2020 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 23 जुलाई 2020।
5. ''कोविड-19 : भारत में 'लॉकडाउन' से प्रवासी कामगारों पर भारी मार'', संयुक्त राष्ट्र समाचार, 2 अप्रैल 2020।
6. गाँधीजी राय, ''चीन के साथ सैन्य मोर्चा तथा भारतीय रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियाँ'', *लोक प्रशासन* (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, अर्धवार्षिक शोध पत्रिका, जनवरी-जून 2021, ISSN:2249-2577), पृ. 16
7. *दैनिक भास्कर* (पटना, 26 सितंबर 2021), पृ. 1
8. गाँधीजी राय, *राजनीतिक सिद्धांत* (पटना, भारती भवन, 2012), पृ. 408
9. उपरोक्त
10. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत, 12 जुलाई 2020, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIEB), दिल्ली।
11. *दैनिक भास्कर* (पटना, 26 सितंबर 2021), पृ. 1
12. *आज* (पटना, 12 जनवरी 2022), पृ. 12